जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 31 संख्याः 309 प्रभात उदयपुर, बुधवार 11 सितम्बर, 2024 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सियोल (कोरिया) पहुँचा। सियोल में कोरियन स्टोन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री की कोरियन स्टोन एसोसिएशन के व्यापारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ राउण्ड टेबल वार्ता हुई।

कोरियन कम्पनियों ने स्वास्थ्य सेवा, माइनिंग, स्टोन, सौर ऊर्जा व कार्बन फाइबर में रुचि दिखायी

मुख्यमंत्री भजनलाल की सैमसंग, एल एक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन से महत्वपूर्ण चर्चा हुई

- मुख्यमंत्री ने कोरियन स्टोन एसोसिएशन को ''इण्डिया स्टोन मार्ट-2026'' के लिये जयपुर आने का आमंत्रण दिया।
- सियोल तकनीकी हाई स्कूल और राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन के बीच सहयोग की भी चर्चा हुई।

सियोल, 10 सितंबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दूसरे दिन कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने प्रदेश में अवसरों की तलाश करने और राज्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में अपनी रुचि दिखायी है। इसमें सैमसंग हेल्थकेयर, एलएक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन, ह्योसंग कॉरपोरेशन के साथ-साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल के संग चर्चा के दौरान, सैमसंग हेल्थकेयर ने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नए हेल्थकेयर डिवाइसेज उपलब्ध कराने में अपनी रुचि दिखायी। वहीं, ओरियन कॉरपोरेशन ने अपने भिवाड़ी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट की चर्चा करते हुए राजस्थान के लिए अपनी विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। एक अन्य दक्षिण कोरियाई फर्म एलएक्स इंटरनेशनल ने राज्य के माइनिंग सेक्टर में काम करने की इच्छा जताई, खास कर लाइमस्टोन (स्टील ग्रेड), सिलिका, जिप्सम, लिग्नाइट, रेयर अर्थ मिनरल्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। एक अन्य प्रमुख दक्षिण कोरियाई फर्म ह्योसंग कॉरपोरेशन भारत में स्थानीय स्तर पर कार्बन फाइबर उत्पादन करने पर विचार कर रही है।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कोरियन स्टोन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक राइंडटेबल डिस्कशन में भी आज भाग लिया, जिसमें तकनीकी सहयोग, राजस्थान में उत्पादित स्टोन्स की खरीद/वितरण और प्रदेश से निर्यात बढ़ाने पर चर्चा की गई। कोरियन स्टोन एसोसिएशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है, के बीच सहयोग बढ़ाने की भी संभावनाओं पर भी चर्चा की गयी। कोरिया स्टोन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर में राजस्थान का दौरा करेगा। इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें फरवरी 2026 में जयपुर में आयोजित होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में भी आमंत्रित किया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सियोल तकनीकी हाई स्कूल का भी आज दौरा किया और राजस्थान के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली उल्लेखनीय पहलों, स्कूल के एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा, छात्रों के साथ बातचीत की और कक्षाओं में सिखाई जा रही अत्यधिक उन्नत तकनीक का अनुभव किया।

एक दिन पहले ही सियोल इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार पर बहुत जोर दे रही है।

इन बैठकों के साथ, राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अपना दक्षिण कोरिया दौरा पूरा कर लिया है और अब 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह प्रतिनिधिमंडल अब जापान की यात्रा करेगा। मुख्यमंत्री के साथ दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग और वाणिज्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी ग्रुप ने बांगलादेश को चेतावनी दी

अडानी ग्रुप के अनुसार, बांगलादेश की सरकार को 500 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप को देने हैं, बांगलादेश के गोड्डा क्षेत्र में 1600 मैगावॉट का बिजलीघर स्थापित करने के लिए

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। अडानी ग्रुप ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को एक प्रमुख बिजली परियोजना से संबंधित 500 मिलियन डॉलर के बकाया ऋण के बारे में चेतावनी दी है। यह कदम संभावित रूप से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को खराब कर सकता है।

फायनैंशियल टाइमस के अनुसार अडानी ने इस स्थिति को ''अस्थिर'' बताया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद सत्ता में आए यूनुस के प्रशासन के लिए लगातार समस्याजनक होती जा रही है।

यूनुस प्रशासन ने हसीना द्वारा किए गए, बुनियादी ढांचों के कई महंगे सौदों की आलोचना की है। जिनमें, भारत में 1,600 मैगावॉट के गोड्डा संयंत्र से कोयले से बनने वाली बिजली की आपूर्ति के लिए अडानी पावर के साथ एक विवादास्पद अनुबंध भी शामिल है।

- अडानी ग्रुप के अनुसार, यह स्थिति अब चलने वाली नहीं है, तथा शेख हसीना का तख्ता पलटने के बाद तथा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद और जटिल होती जा रही है।
- जैसा कि विदित ही है, बांगलादेश 3.7 अरब डॉलर के ऋण के भार से दबा हुआ है पावर सैक्टर में
- बांगलादेश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने के प्रयास में है, पावर सैक्टर को वित्तीय नुकसान के गर्त से निकलकर, इस सैक्टर में कुछ स्थिरता लाने के लिए।

बताया कि घटना को लेकर 24 मार्च, 2021 को पीडिता की मां ने हरमाडा थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि एक दिन पहले वह पडोस के मकान में किराए पर रहने वाले विक्रम को पानी के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।

बढ़ते वित्तीय दबावों के बावजूद, अडानी पावर, बांग्लादेश को रिलायबल एनर्जी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा है कि वह बांग्लादेशी सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है और उन्हें वर्तमान स्थिति के ''अनसस्टेनेबल नेचर'' के बारे में सूचित कर दिया है।

यह वित्तीय तनाव बांग्लादेश में व्यापक ऊर्जा संकट का हिस्सा है, जिसका बिजली से संबंधित ऋण 3.7 बिलियन डॉलर हो गया है। यूनुस के मुख्य ऊर्जा सलाहकार, मोहम्मद फौज़ुल कबीर खान ने खुलासा किया कि बांग्लादेश पर अडानी का 492 मिलियन डॉलर बकाया है। अंतरिम सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता मांग रही है।

बांग्लादेश के तेजी से बढत्रते विकास में, लगातार ऊर्जा की कमी के कारण बाधा आ रही है, जो कि घटते घरेलू गैस भंडार के कारण बदतर हो गई है। आलोचकों का तर्क है कि पिछली सरकार खुली निविदाओं से बचती रही, जिसमें अकुशलता और भ्रष्टाचार को बढ़ाकर समस्या को और बढ़ा दिया। अडानी पावर, जिसका सैमिकंडक्टर परियोजना में 10 बिलियन डॉलर का निवेश है, बिजली समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। अडानी ने बांग्लादेश से बिजली को दूसरी जगह भेजने की किसी भी योजना से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि गोड्डा संयंत्र अभी तक भारतीय ग्रिड से जुड़ा नहीं है।

अंतरिम सरकार पिछले ऊर्जा समझौतों की समीक्षा करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बोली को फिर से शुरू करना और वित्तीय निगरानी को बढ़ाना है। इसके बावजूद, सरकार भारत औश्र चीन, दोनों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म, अभियुक्त को 20 साल की सजा

जयपुर, 10 सितंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विक्रम सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एम.डी. शर्मा ने

- अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता ने सुनवाई के दौरान दुष्कर्म की बात कही और मैडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

थरुर के खिलाफ मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केस दायर करने वाले भाजपा नेता को नोटिस भी दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। शशि थरूर ने नवम्बर 2018 के लिटरेचर फैस्टिवल में बैंगलोर में प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, ''शिवलिंग पर बिच्छु बैठा है।''

थरूर के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगाने के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर.महाजन की बैंच ने दिल्ली पुलिस और भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा। राजीव बब्बर ने ही थरूर के खिलाफ शिकायत की थी।

बैंच ने चार सप्ताह के लिए नोटिस जारी किया। अगले आदेश तक मानहानि की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

थरूर की तरफ से उपस्थित हुए एक वकील ने कहा कि यह बयान असल में वर्ष 2012 में कारवां मैगजीन

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने 2018 में बंगलौर लिटरेचर फैस्टिवल में कथित तौर पर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी कि ''शिवलिंग पर बिच्छु बैठा है,'' जिस पर दिल्ली के एक भाजपा नेता ने थरूर के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया था।
- ट्रायल कोर्ट में हो रही सुनवाई पर अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, पर, हाल ही में 29 अगस्त को हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर रद्द कर ट्रायल कोर्ट को सुनवाई की अनुमति दे दी, जिसके खिलाफ शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

में छपे एक लेख में या बाद में 2018 में थरूर ने भी वही बात कही थी।

थरूर ने हाईकोर्ट के अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी।

हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में थरूर के खिलाफ मानहानि में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी बाद में 29 अगस्त को कोर्ट ने अपना अंतरिम स्टे ऑर्डर वापस ले लिया और कहा कि थरूर 10 सितम्बर को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हों।

ट्रायल कोर्ट ने थरूर को बब्बर द्वारा दायर मानहानि से सम्मन दिया था। थरूर ने 2018 में बैंग्लोर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि ''मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छु हैं।''

'राहुल के खरे सच से हताश है भाजपा'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा का इकोसिस्टम हताश और पस्त हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने खरा सच बोल दिया है। ''मोदी-बुलबुला'' फूट चुका है। उनकी डर की राजनीति असफल हो गई है तथा कोई भी उन्हें या उनके चियरलीडर्स के ग्रुप को गम्भीरता से नहीं ले रहा है।

- कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ''मोदी बुलबुला'' फूट गया है उनकी डर की राजनीति विफल हो गई है। राहुल के इस सच पर भाजपा तिलमिला रही है।

उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी ने भाजपा-आर.एस.एस. की नफरत और विभाजन की खतरनाक राजनीति के बारे में बार-बार सचेत किया है। उनका सम्पूर्ण मिशन सार्वजनिक संवाद में प्रेम,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गृहिणी की सड़क दुर्घटना होने पर भी मिलेगा मुआवजा

जयपुर, 10 सितंबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मोटर दुर्घटना प्रकरणों में घायल और मृतक के आश्रितों के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए गाइड लाइन-2024 जारी की गई है। इसके तहत अब घरेलू

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोटर दुर्घटना प्रकरणों में घायल व मृतक के आश्रितों से संबंधित मुआवजा के त्वरित निस्तारण के लिए गाइडलाइन 2024 जारी की गई है, उसमें उक्त निर्देश दिया गया है।

महिला की मृत्यु होने पर भी उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में राज्य सरकार के श्रम विभाग की ओर से प्रचलित वार्षिक न्यूनतम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वॉशिंगटन की युनिवर्सिटी में राहुल के भाषण ने, एक बार फिर हंगामा खड़ा किया भारत में

कांग्रेस के अनुसार, राहुल गाँधी ने कहा कि, मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता, पर मेरे उनके बीच विचारों का मतभेद है और उनके और मेरे नज़रिए में बहुत फर्क है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस समय चार दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, ने भारतीय अमेरिकन समुदाय को संबोधित करते हुये कहा कि प्रेम, सम्मान एवं विनम्रता भारतीय राजनीति से गायब हो रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नफरत नहीं करते, बल्कि अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदी के विचारों से असहमत हैं।

उन्होंने वॉशिंगटन डी.सी.-स्थित जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में बातचीत के दौरान कहा, ''मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता। उनका एक दृष्टिकोण है, मैं उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे घृणा नहीं करता। उनकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है।

इस बीच, बेरोज़गारी, धार्मिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तीकरण तथा आर.एस.एस. जैसे मुद्दों पर उनकी टिप्पणियों को लेकर भाजपा वाक् युद्ध पर उतर आई है। राहुल गांधी के संबोधन के संदर्भों से कुछ खास शब्दों ने छाँटकर, भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वे विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं।

सत्तारूढ़ पार्टी के मीडिया रणनीतिकारों ने गांधी पर हमले करे के लिए केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मैदान में उतार दिया है। पूर्व राजनयिक पुरी ने संदर्भ को छोड़कर राहुल गांधी के कुछ बयान छाँटे हैं तथा उनको उद्धृत करते हुये राहुल पर आरोप लगाया है कि वे विदेश में ''खतरनाक बातें'' फैला रहे हैं।

पुरी ने इस मुद्दे पर एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुये कहा, ''मेरे विचार से यह बहुत ज्यादा अनर्थकारी है। उनके सामने बैठे लोग मेरे समुदाय के थे। वे लोग अमेरिका में जैसे-तैसे जीवन-यापन कर रहे हैं तथा अपने देश के साथ उनका कोई खास जुड़ाव नहीं रहा है और राहुल जी उनके बीच झूठी बातें कह रहे हैं।''

- कांग्रेस के अनुसार, राहुल गाँधी ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि हमारी लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। यह तो सतही बात है। लड़ाई इस बारे में है कि, एक सिख को पगड़ी बांधने की, कड़ा पहनने की, गुरुद्वारा जाने की इजाज़त है कि नहीं। यह लड़ाई केवल सिखों के बारे में नहीं, बल्कि हर धर्म के बारे में है।
- भाजपा ने राहुल की टिप्पणी का जवाब देने के लिए केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उतारा। हरदीप पुरी ने कहा, ''सिखों को उनके अस्तित्व पर खतरे का केवल उस समय सामना करना पड़ता था, जब राहुल गाँधी के परिवार का शासन था।''
- प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की उनके अंगरक्षक द्वारा हत्या करने के बाद 3000 सरदार मारे गए थे, जिंदा जला दिए गए थे। अतः नेहरू-गाँधी परिवार को सिखों की स्वतंत्रता व सुरक्षा की बात अपमानजनक लगती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)